Shri S. N. Chaturvedi: How is it, when the hon. Minister says that these import licence forms are as good as currency notes, no check was kept on them and this racket or this theft was only detected.....

Mr. Speaker: Currency notes can also be stolen.

Shri S. N. Chaturvedi: How was it that this came to their notice only after a year or so?

Shri Manubhai Shah: Sir, when thefts take place even from a well locked up treasury, theft of forms like these, which are in use continuously like currency notes, where some forms are written, some books are lying on the table and things like that and some people tear off and take some forms away, it can only be noticed when the whole thing is done, when the forms stolen are actually made use of.

Shri Warior: May I know whether the persons involved in this racket are the usual import licence holders or somebody else who have operated through the usual licence holders?

Shri Manubhai Shah: Out of more than 7 lakhs to 10 lakhs people holding import licences, whether a particular licence holder is a thief or not we cannot suspect. What we can say is that the few people who are involved in this will be brought to book.

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में कितने कस्प्रिट्स अंडर कस्टडी हैं और कितनों पर मुकदमा चल रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : सवालों के जो जवाब दिये जायें, माननीय सदस्य उन को ध्यान से सुनें ।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या यह सही है कि जिन लोगों को इम्पोर्ट लाइसेंसिज दिये जाते हैं, वे अपने इम्पोर्ट लाइसेंसिज दूसरे लोगों को बेच भी देते हैं; यदि हां, तो इस की रोक-थाम के लिए सरकार के द्वारा क्या उपाय किया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : इस की कोई इजाजत नहीं है । ये इम्पोर्ट लाइसेंस नान-ट्रांसफ़रेबल कैरेक्टर के हैं ।

श्री सरजू पाण्डेय : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में कितना धन इन्वाल्व्ड है ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत थोड़ा है । शायद मिनिस्टर साहब बताना नहीं चाहते हैं ।

श्री सरजू पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, यह बताने में क्या आपत्ति है ।

Foreign Trade

+

*181. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shrimati Sharda Mukerjee:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri S. M. Banerjee:
Shri Yashpal Singh:
Shri P. C. Borooah:
Shri D. C. Sharma:
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri Shiv Charan Gupta:

Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether it is a fact that stagnant exports and increased imports recently have been responsible for a deterioration in India's foreign trade;

(b) if so, its impact on the balance of trade and payments; and

(c) the further steps taken to improve it?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-5130/65].

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जैसा कि इस वक्तव्य के अन्तिम पैराग्राफ़ में निर्देश दिया गया है, जो भारतीय दूसरे देशों में जा कर बस

गये हैं, उन का धन अधिक से अधिक मात्रा में भारत में आ कर लगे, जिस से विदेशी मुद्रा का भारत के हक में प्रयोग हो सके, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : उसी के लिए हम ने नेशनल डिफेंस रेमिटेंस स्कीम का एलान किया है, जिस के द्वारा जो भारतीय या बिन-भारतीय विदेशों से यहां विदेशी मुद्रा लाना चाहते हैं, उन को साठ परसेंट मुद्रा को इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जो एक्सपोर्ट इन्सेन्टिव स्कीम है, क्या इस के द्वारा सरकार को कुछ ऐसी जानकारी भी मिली है कि भ्रष्टाचार बराबर बढ़ रहा है, यदि हां, तो उस को नियंत्रण में करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : जैसे समाज के और हिस्सों में थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार चलता है, वैसे ही विदेशी मुद्रा के बारे में चलता है । इस क्षेत्र में वह ज्यादा है, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : इस बात को देखते हुए कि हमारी आयात और निर्यात नीति में कुछ न कुछ दोष है क्या सरकार इस नीति पर फिर से विचार करेगी, ताकि यह दोष न रह जाये ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक निर्यात की नीति का सम्बन्ध है, उत्पादन बढ़ेगा, तो निर्यात अपने आप बढ़ेगा । जब उत्पादन ही कम हो, तो किस चीज का निर्यात किया जाये ?

श्री यशपाल सिंह : पिछले साल की अपेक्षा इस साल एक्सपोर्ट में दो करोड़ रुपये की कमी हो गई है । इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मनुभाई शाह : आने वाले महीनों में जब एग्रीकल्चरल क्राप्स बाहर आयेंगी, तो हमें आशा है कि एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो घाटा हुआ है, उस को हम पूरा करेंगे और हम दोबारा उसी मात्रा में एक्सपोर्ट करेंगे, जो कि पहले कर रहे थे ।

Shri P. C. Borooah: Last year the country spent Rs. 425 crores more on imports than what it earned by way of exports. May I know whether this matter was referred to the Import Substitution Committee; if so, what their recommendations are and the Government's decision thereto?

Shri Manubhai Shah: The Import Substitution Committee can only cut out imports of items which are produced in the country or which can be produced in the country. But when foodgrains are to be imported to the extent of Rs. 300 crores and oil and various other things have also to be imported over and above our defence requirements, naturally the Import Substitution Committee cannot hold up the whole thing.

Shri P. R. Chakraverti: May I know whether the discrepancy between the anticipated and actual figures of exports is caused by the fact that exports of commodities through the different ports in the country are taken into account as exports as such?

Shri Manubhai Shah: There is no relationship between the two. What the hon. Member is perhaps referring to is the actual figure of realisation as reported by the Reserve Bank and DGCI. That is a minor difference that occurs in the case of every country in the world. Here also the figures given by the Reserve Bank are sometimes higher and sometimes lower by Rs. 10 crores or so.

श्री हुकम चन्द कछवाय : हमारा जो व्यापार चीनी का विदेशों से है उस में कोई विशेष लाभ नहीं होता । इसलिये यहां की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उस का विदेशों से व्यापार बन्द करने के बारे में सोच रही है ?

श्री मनुभाई शाह : चीनी का व्यापार विदेशों से बन्द करना हिन्दुस्तान की कुसेवा करना है । चीनी के एक्सपोर्ट से जो फारेन एक्सचेन्ज हम को मिलता है वह हम को चीनी का खाना कम कर के भी लेना होगा ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या गवर्नमेंट के पास एक्सपोर्टर्स से ऐसी शिकायतें आई हैं कि रिजर्व बैंक की ओर से बड़ी कठिनाई आती है एक्सपोर्ट करने वाले लोगों के रास्ते में । चूंकि इस के लिये इन्सेन्टिव की जरूरत है इसलिये क्या सरकार ने रिजर्व बैंक के अधिकारियों से कुछ बात की है ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक इन्सेन्टिव या असिस्टेंस का ताल्लुक है इसे के बीच में रिजर्व बैंक नहीं आता है । यह काम सिर्फ भारत सरकार का है । इस सम्बन्ध में कुछ तकलीफ जरूर हुई है क्योंकि पैसा वगैरह मिलने में देर लगती है । इसके लिये सरकार काफी कोशिश कर रही है और कई दफे सदन के सामने प्रस्ताव भी रखे गये हैं । जहां तक रिजर्व बैंक का ताल्लुक है, जिन लोगों को बाहर जाना होता है जैसे कि सेल्समैन, कामर्शल ट्रैवेलर्स, प्रिजेन्टेटिव्ज आदि, उन को कुछ कठिनाई होती है क्योंकि इस में रिजर्व बैंक कुछ संकुचित जरूर है । इसके लिये हम रिजर्व बैंक से कह चुके हैं कि वह कुछ उदार हो ।

Shrimati Savitri Nigam: How far is this correct that one of the reasons for the downward trend in our export earnings is also the decrease in the price of raw materials in the world market?

Shri Manubhai Shah: What the hon. lady Member says is normally correct. Sugar is an obvious example. It was selling at pound 107 per ton last year, that is, about Rs. 1,400. Today the world price is Rs. 250. It has sunk to that extent. So also is the case of iron ore. While that is one of the factors, by and large the real answer is more production being made available for exports.

Shrimati Renuka Ray: Has the Minister instituted any enquiry as to how far the discrepancy is due to certain fraudulent procedures in regard to import entitlements and who is actually responsible for this?

Shri Manubhai Shah: There is hardly any relationship between the small value of import entitlement and the need to grow exports phenomenally, even beyond what we have achieved in the last three years. As I mentioned in the statement, increasing it from Rs. 600 crores to over Rs. 800 crores or 850 crores was not a small task and our exporters have done it. Regarding the misuse of a minor value of import entitlement, for the last seven or eight years we have made some broad estimates and scrutiny on that also. Out of the total export of more than Rs. 4,000 crores for the last seven or eight years the value of abuse or non-realisation is about Rs. 6.87 crores (Rs. 6 crores and 87 lakhs) which is much less than the average of any other country in regard to non-realisation.

Shri Hem Barua: Is it a fact that during the recent crisis on account of Pakistani aggression due to facts like dislocation of shipping, impounding of cargoes and general insecurity in the country our exports registered a further decline as compared to our exports during September of earlier years? What is the volume of our export during the crisis?

Shri Manubhai Shah: When the hostilities began in September we were afraid that there will be a large-scale fall in our exports because of the impounding of cargoes, because of the ships being detained and large quantities of tea and jute being confiscated and frozen by Pakistan, because of bombing and various other reasons. But, thanks to the dock workers and shipping and port authorities and the vigour of the exporters, the exports in September were practically of the same order, namely, Rs. 70·8 crores as compared to Rs. 72.8 crores last year.

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने जो हिन्दुस्तान के जहाजों को रोका है, खास कर असम से आने वाले चाय वगैरह के जहाजों को, उस के बाद हमारे देश से चाय का एक्सपोर्ट होता रहे इस का क्या इन्तजाम हो रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : जो माल गया है उस के लिये तो रिटैलिएटरी ऐक्शन ही हो सकता है। लेकिन चाय की क्राप इस साल अच्छी है इस लिये उस का एक्सपोर्ट घटने की सम्भावना नहीं है बल्कि मैं समझता हूं कि दो या तीन करोड़ रु० के करीब बढ़ेगी ही । जूट के बारे में हमें ज्यादा सफर करना पड़ा । लेकिन हम पन्द्रह लाख गांठें इम्पोर्ट कर रहे है । दस लाख गांठे थाईलैंड से और पांच लाख गांठें और जगहों से इम्पोर्ट कर रहे हैं क्योंकि जूट जब एक्सपोर्ट बहुत बढ़ रहा है ।

श्री विशन चन्द्र सेठ : मैं निवेदन करता हूं कि आप ने जो रिपोर्ट दी है उस में आप ने बतलाया है कि जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तब तक कोई डेवेलपमेंट नहीं हो सकता है जिस में कि फारेन कंट्रीज को हम ज्यादा माल भेज सकें । तो जो प्रोडक्शन कम हो रहा है इस के लिये तो जरूरी है कि गवर्नमेंट उन को सपोर्ट करे, प्रापर वातावरण बनाये और सारे साधन इकट्ठा करे । गवर्नमेंट को इस को कंसीडर करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त आप निवेदन न करके सवाल पूछ सकते हैं ।

Shri Manubhai Shah: It is a suggestion for action.

Shri U. M. Trivedi: It will be a good thing for the country to know what retaliatory measures the Government have taken to reimburse us for the losses sustained by the seizing of these goods by Pakistan.

Mr. Speaker: That statement was made by Shri Raj Bahadur.

Shri Hem Barua: We want a reply by Shri Manubhai Shah.

Mr. Speaker: Shri Venkatasubbaiah.

Shri P. Venkatasubbaiah: We find from the note that has been given by the Ministry that the decerase in our exports is due to the decrease in the production of agricultural commodities. May I know whether the Government proposes to rationalise both imports and exports, for instance, by importing more chemical fertilisers to boost up agricultural production? What is the Government doing in that direction?

अध्यक्ष महोदय : आप कहां से कहां चले गये ।

Shri Manubhai Shah: The import of fertilizers is much larger than in the past.

Property of Indians taken over by Pakistan and *vice versa*

***182. Shri Shree Narayan Das:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the nature and extent of property both immoveable and moveable owned by the Pakistani nationals, taken over by Government as a sequel to the India-Pakistan conflict; and

(b) the nature and extent of such property of Indians taken over by the Pakistan Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy): (a) Orders have been issued vesting in the Custodian of Enemy Property in India all immoveable and certain categories of moveable properties belonging to or held by or managed on behalf of Pakistani nationals. A statement indicating the properties in these categories so far taken over by him is laid on the Table of the House. A large number is, however, in the process of being taken over.